कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया अब नहीं रुकेगी : डॉ. यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया अब लगातार जारी रहेगी। सभी पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए इस वर्ष सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मंत्रालय परिसर में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के हित और उनके प्रमोशन के साथ सरकार ने अपना भावनात्मक जुड़ाव रखते हुए निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत प्रदेश के विकास और जनकल्याण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पदोन्नति मिलने से कर्मचारियों में उत्साह बढ़ता है और उनके परिवारों में भी खुशी का माहौल बनता है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी जागृति पटेल और विक्रम अवॉर्ड विजेता अंजली वर्मा को सम्मानित किया। विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के साथ उनके आवास और कल्याण से जुड़े विषयों पर भी ध्यान दे रहे हैं।

मंत्रालय परिवार की ओर से सुभाष वर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने कर्मचारी हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कार्यक्रम में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

रबी सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तैयारी के निर्देश

नप्र, भोपाल : ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आगामी रबी सीजन में किसानों को मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों से ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा। निर्देश दिए कि बिजली सामग्री के भंडार में किसी भी जरूरी उपकरण की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पावर ट्रांसफार्मर पर बढ़ते भार को कम करने के लिए कार्ययोजना बनाने और फीडरों में ट्रिपिंग की समस्या को कम करने के प्रयास करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों से उपलब्ध सामग्री की जानकारी ली और लापरवाही नहीं बरतने को कहा। प्रमुख सचिव ऊर्जा मनीष सिंह ने उपभोक्ता संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए रबी सीजन की तैयारियां पहले से पूरी करने के निर्देश दिए।

डिजिटल सेवाओं से बेहतर होगी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच : राजेन्द्र शुक्ल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल व्यवस्थाओं से नागरिकों को पारदर्शी और सरल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

श्री शुक्ल कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मॉडल जिला और मॉडल स्वास्थ्य संस्था पहल को केवल तकनीकी परियोजना न मानते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव के अभियान के रूप में लागू किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखों के शत-प्रतिशत उपयोग, तकनीक के प्रभावी समावेश और नागरिक केंद्रित सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए टेलीमेडिसिन का अधिक उपयोग करने पर भी जोर दिया गया।

कार्यक्रम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों और स्वास्थ्य संस्थानों को सम्मानित किया गया। आभा आईडी निर्माण में जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और सतना को सम्मान मिला। वहीं टोकन जनरेशन और स्वास्थ्य अभिलेख फाइलिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को भी सम्मानित किया गया।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रभावी हिस्सा बनाया जाए। आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद शाह ने बताया कि अगस्त 2026 तक प्रदेश में 5 करोड़ 90 लाख से अधिक आभा आईडी और 20 हजार से अधिक स्वास्थ्य संस्थाओं का पंजीयन किया जा चुका है।

मालनपुर में गॉदरेज की चौथी विनिर्माण इकाई का आज शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 26 अगस्त को भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गॉदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की विस्तारित चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। इस इकाई के विस्तार पर 450 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। इससे

- **450 करोड़ के निवेश से मिलेंगे रोजगार अवसर**

क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ 2,250 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

नई इकाई में आधुनिक तकनीक आधारित उत्पादन संयंत्र और स्वचालित पैकेजिंग प्रणाली स्थापित की जा रही है। इसके माध्यम से हेयर कलर, मच्छर निरोधक उत्पाद और एयर फ्रेशनर सहित अन्य उत्पादों के निर्माण की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे भिंड और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

गॉदरेज के मालनपुर संयंत्र में साबुन, हेयर कलर और घरेलू कीटनाशक जैसे उत्पादों का निर्माण किया जाता है। कंपनी ने यहां अब तक करीब 850 करोड़ रुपये का निवेश किया है। विस्तार के बाद संयंत्र की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यह एशिया की बड़ी एकीकृत साबुन निर्माण इकाइयों में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

उज्जैन में मंगलवार को सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल के पदभार ग्रहण समारोह में उन्हें संभाग आयुक्त आशीष सिंह एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नवीन दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

25 ब्रॉंड के घी के नमूने अमानक मिले

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः रक्षाबंधन और आगामी त्योहारों को देखते हुए मध्यप्रदेश में दूध, घी, मावा और मिठाई की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के आठ शहरों में 25 ब्रांड के घी के नमूने अमानक पाए गए हैं। जांच में घी में पॉम ऑयल समेत अन्य मिलावट सामने आई है।

जांच में भोपाल के नौ, इंदौर के सात और उज्जैन के तीन घी के नमूने अमानक मिले हैं। इसके अलावा कटनी, नर्मदापुरम, डिंडौरी, धार और दमोह में भी घी के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।

- **भोपाल, इंदौर समेत आठ शहरों में जांच के दौरान पाई गई मिलावट**
- **खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुरू की कार्रवाई**
- **भोपाल में जब्त मिल्क केक नागपुर के मनन स्वीट्स का था**

खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुजरात के खेड़ा जिले की बालाजी डेयरी प्रोडक्ट्स के घी के नमूने भी जांच में असुरक्षित पाए हैं। इस संबंध में गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखकर निर्माता के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है।

भोपाल में सोमवार को नादरा बस स्टैंड से जब्त किया गया 166 किलो मिल्क केक भी जांच में अमानक पाया गया है। यह मिल्क केक महाराष्ट्र के नागपुर से आया था। खाद्य सुरक्षा नियंत्रक मनोज पुष्प ने नागपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। जांच में सामने आया कि भोपाल में जब्त किया गया मिल्क केक नागपुर के स्नेहदीप कॉलोनी, नारा रोड, जरीपटका स्थित मनन स्वीट्स से लाया गया था। इससे पहले कार्रवाई के दौरान 150 किलो मावा और 166 किलो मिल्क केक जब्त किया गया था।

अजा कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएं : चौहान

नप्र, भोपाल : अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

श्री चौहान ने मंत्रालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में योजनाओं और कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने भिंड, मुरैना, शाजापुर और विदिशा में स्वीकृत कन्या छात्रावासों के निर्माण कार्य जल्द शुरू करने को कहा। साथ ही निर्माण में आ रही समस्याओं का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय से समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण और आवास सहायता योजना की समीक्षा की गई। मंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर छात्रवृत्ति से जुड़ी शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

यूपीआई का एक दशक : मुख्यमंत्री ने दी बधाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के सफल एक दशक पूरा होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उपयोगकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को नई गति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीआई का लेनदेन 1.78 करोड़ से बढ़कर अब 24 हजार करोड़ से अधिक तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यूपीआई केवल डिजिटल भुगतान का माध्यम नहीं, बल्कि छोटे दुकानदारों से लेकर वैश्विक बाजारों तक सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था का सशक्त माध्यम बन चुका है।

ग्रीन चेक वाले नर्सिंग कॉलेजों में ही होगी परीक्षाः सुप्रीम कोर्ट

- **जांच में अयोग्य पाए गए संस्थानों के छात्रों को दूसरे कॉलेजों में किया जाएगा शिफ्ट**

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और गुणवत्ता को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच में 'ग्रीन चेक' मिलने वाले कॉलेजों के छात्र ही अपने संस्थान में परीक्षा दे सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कॉलेजों को सीबीआई जांच में हरी झंडी नहीं मिलेगी, वहां के छात्रों को अन्य उपयुक्त संस्थानों में शिफ्ट किया जाएगा। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने छात्रों से कहा कि वे उस कॉलेज प्रबंधन से सवाल करें, जिसे उन्होंने फीस, डोनेशन या अन्य राशि दी है।

छात्रों की ओर से पेश वकील ने बताया कि 2020-21 और 2021-22 शैक्षणिक सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों के कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित समिति ने तय मानकों के अनुसार पाया था। उन्होंने छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने की मांग की। मध्यप्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार के अनुसार, नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। ग्वालियर-चंबल संभाग के करीब 130 कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच पर रोक की मांग की थी। प्रदेश के अन्य कॉलेजों की जांच के बाद उन्हें उपयुक्त, अनुपयुक्त और कमियां वाले कॉलेजों की श्रेणी में रखा गया था।

ग्वालियर कृषि में बनेगा अग्रणी, पंजाब-हरियाणा को देगा चुनौती : डॉ. यादव

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर कृषि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में पंजाब व हरियाणा से भी आगे पहुंचने की क्षमता रखता है। डॉ. यादव ने डबरा में आयोजित 'बलराम कृषि महोत्सव' को वर्चुअली संबोधित करते हुए किसानों को आधुनिक खेती और नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने ने कहा कि ग्वालियर शिक्षा, रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश का प्रमुख केंद्र बन रहा है। क्षेत्र की सरसों, गेहूं, मसूर और चने की गुणवत्ता ने देशभर में पहचान बनाई है।

• मजबूरी है, सब कुछ सहना पड़ेगा...

साहब की ठसक ऐसी कि बिना इजाजत परिंदा भी आसपास न फटके। आम आदमी फरियाद लेकर पहुंचने में पसीना बहाता है, लेकिन पिछले दिनों सत्ताधारी दल से जुड़े कुछ युवकों ने साहब के दफ्तर में घुसकर शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसा सब कुछ कर दिया। सत्ता का साथ हो तो साहब भी खून का घूंट पीकर रह गए।

• नियम-कानून हम सिखाएंगे...

एक स्थानीय निकाय की बैठक में संवैधानिक पद पर बैठे माननीय ने प्रशासनिक मुखिया को खूब खरी-खोटी सुनाई। साहब शांत रहे और नियमों का हवाला देते रहे। अब यदि साहब ने सच में नियम लागू कर दिए तो माननीय की कई ऐसी सुविधाओं पर कैंची चल सकती है, जो नियमों की किताब में कहीं दिखाई ही नहीं देतीं।

• साहब से पंगा भारी पड़ गया...

अचानक एक विभाग में छापों की बाढ़ आ गई। वजह न जनता का हित था, न मिलावटी खाद्य सामग्री। असली कारण एक बड़े साहब की नाराजगी बताया जा रहा है। चुनिंदा ठिकानों पर कार्रवाई और फिर मीडिया में उसका जोरदार प्रचार कहानी खुद कह रहा है।

• साहब की गाड़ी का इंटीरियर...

एक साहब को समकक्ष की नई सरकारी गाड़ी का इंटीरियर इतना भाया कि अपने लिए भी वैसा ही फरमान जारी कर दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि समकक्ष मलाईदार कॉरपोरेशन में हैं, जहां पसंद को जरूरत और जरूरत को व्यवस्था बनने में देर नहीं लगती।

• समय पर हाजिरी के लिए हाईटेक व्यवस्था...

मंत्रालय में समय पर हाजिरी के लिए ई-अटेंडेंस शुरू हुई तो कुछ साहबों ने तकनीक को भी मात दे दी। हाजिरी समय पर लग रही है, लेकिन साहब घर पर आराम फरमाते मिल रहे हैं। अब तकनीक कमाल कर रही है या कोई और 'व्यवस्था', जांच का विषय है।

• तबादले ने बढ़ाई दूरियां...

बड़े फेरबदल में युवा जोड़े की पोस्टिंग उत्तर-दक्षिण हो गई। कुर्सियां दूर हो गईं, लेकिन दिलों की दूरी अभी नहीं बढ़ी। विभाग बदले हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं।

महिला आरक्षक वर्षा पटेल ने माउंट एल्ब्रुस पर फहराया तिरंगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश पुलिस की महिला आरक्षक वर्षा पटेल ने यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। जबलपुर में पदस्थ आरक्षक वर्षा पटेल ने 21 अगस्त 2026 को 18,510 फीट ऊंची माउंट एल्ब्रुस चोटी को सफलतापूर्वक फतह किया।

कठिन मौसम, तेज हवाओं और कड़ाके की ठंड के बीच वर्षा पटेल ने साहस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए सुबह 9 बजकर 7 मिनट पर शिखर पर पहुंचकर भारत का तिरंगा और मध्यप्रदेश पुलिस का ध्वज फहराया।

पुलिस महानिदेशक कैलाश

मकवाणा ने वर्षा पटेल को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे पुलिस विभाग के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि वर्षा पटेल का साहस और संघर्ष प्रदेश की बेटियों और पुलिस बल की महिला सदस्यों के लिए प्रेरणा है।

मध्यप्रदेश में अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एनजीटी सख्त

नदियों में गंदा पानी पहुंचने पर राज्य सरकार से मांगी सत्यापन रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के पालन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार को सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने मुख्य सचिव से इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने की। यह मामला मूल आवेदन संख्या 606/2018 के तहत चल रहा है, जिसमें नगर निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन और पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। एनजीटी ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र का परीक्षण किया। अधिकरण ने पाया कि प्रदेश में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति 413 नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है, जिनका पर्याप्त मैदानी सत्यापन नहीं किया गया है। इसके बाद एनजीटी ने प्रत्येक जिले के कलेक्टर के माध्यम से आंकड़ों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं।

राज्य शासन के अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 8,467.87 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जबकि 8,412.48 टन के प्रसंस्करण की जानकारी दी गई है। एनजीटी ने कचरे के पृथक्करण, मिश्रित कचरे की कम्पोस्टिंग, कम्पोस्ट की गुणवत्ता और अवशेषों के निपटान में कमियों को रेखांकित किया है।

अधिकरण ने बताया कि 110 निकायों में लगभग 12.86 लाख मीट्रिक टन विरासत अपशिष्ट का उपचार बाकी है, जिसे दिसंबर 2026 तक निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 303 निकायों में शेष विरासत अपशिष्ट के उपचार के लिए भी समय सीमा तय की गई है। अगली रिपोर्ट में प्रसंस्करण और अपशिष्ट स्थलों की जियो-कोडेड तस्वीरें भी प्रस्तुत करनी होंगी।

खेलो इंडिया *नई खेलो इंडिया योजना से ....*

मजबूत होगी खिलाड़ियों की ग्रासरूट से पोडियम तक की राह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नई खेलो इंडिया योजना के तहत वर्ष 2026-31 के लिए 36,441 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) क्षेत्रीय केंद्र, भोपाल और खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि प्रदेश में संचालित 52 खेलो इंडिया केंद्रों को और सशक्त किया जाएगा। भोपाल को प्रमुख खेल केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी जोर रहेगा।

साई क्षेत्रीय निदेशक अभिषेक सिंह चौहान ने बताया कि योजना में जिला स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान,

अधोसंरचना, प्रशिक्षण, खेल विज्ञान और तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में खेल प्रतिभा वाले क्षेत्रों की पहचान कर स्थानीय जरूरतों के अनुसार रणनीति तैयार की जाएगी।

योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, आहार, आवास, खेल किट, यात्रा, चिकित्सा, शिक्षा और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए सहायता मिलेगी। खेल विज्ञान विशेषज्ञों के साथ डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक और पोषण विशेषज्ञ भी खिलाड़ियों को सहयोग देंगे। स्कूलों, उत्कृष्ट विद्यालयों, फीडर स्कूलों और खेलो इंडिया केंद्रों के नेटवर्क से शुरुआती स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। उभरते खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। योजना में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रतिभा खोज, प्रदर्शन विश्लेषण और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर भी जोर रहेगा। खिलाड़ियों को युवा, विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय और अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से अधिक अवसर दिए जाएंगे। फिट इंडिया अभियान के तहत महिलाओं, दिव्यांगजनों और समुदायों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com